सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड

राज्य विधान सभा के वर्ष, 2016 के प्रथम सत्र में

डॉ0 कृष्ण कान्त पाल

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

का

अभिभाषण

देहरादून, बुधवार, 09 मार्च, 2016 (फाल्गुन 19, शक सम्वत्, 1937)

उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण;

उत्तराखण्ड राज्य की तृतीय विधान सभा के वर्ष 2016 के प्रथम सत्र में मैं सर्वप्रथम आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मैं राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि तथा आगामी वर्ष में विकास की नई ऊँचाईयों को प्राप्त करने की कामना करते हुए मैं आप सभी का आहवान् करता हूँ।

मुझे इस बात का हर्ष है कि सरकार के नेतृत्व में सभी राज्यवासी एकजुट होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि दर क्रमशः 11%, 12% तथा 12.7% रही है। वर्ष 2015–16 हेतु (अग्रिम अनुमानों के अनुसार) हमारी प्रतिव्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर ₹ 1.55 लाख हो गई है। हमारी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। महापंजीयक, भारत सरकार की अद्यतन एस0आर0एस0 बुलेटिन के अनुसार राज्य की जन्म दर (18.2) मृत्यु दर (6.4) तथा शिशु मृत्यु दर (32.0) अखिल भारतीय औसत से बेहतर है। इन संकेताकों में हम उन्नत राज्यों के समकक्ष पहुँचने हेतु प्रयासरत हैं। समावेशी विकास की अवधारणा के अन्तर्गत मेरी सरकार जहाँ एक ओर अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के प्रयास कर रही है वहीं दूसरी ओर कृषि एवं बागवानी के सुदृढ़ीकरण, शिक्षा के उन्नयन, पर्यटन एवं संस्कृति की सम्पोषणीयता बनाने, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए प्रयासरत है।

(1) राज्य की भौगोलिक स्थिति, संरचना, प्राकृतिक विशिष्टि तथा जैव विविधता के दृष्टिगत कृषि, औद्यानिकी तथा औषधीय एवं संगध पौध उत्पादन राज्य के लिए महत्वपूर्ण देन है। रोजगार की दृष्टि से अभी भी प्राथमिक सेक्टर पर हमारी अत्यधिक निर्भरता है इसलिए मेरी सरकार ने कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र को पर्याप्त महत्व देते हुए इसके प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनायें प्रारम्भ की हैं। इन योजनाओं से एक ओर प्राथमिक सेक्टर की वृद्धि दर को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रूकेगा तो दूसरी ओर भू–क्षरण की रोकथाम, जल स्रोतों व भू–जल स्तर में वृद्धि होगी। कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:–

- पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय फसलों सहित खेती को प्रोत्साहित करने की योजना चलाई जा रही है।

- मेरी सरकार गहत, काला भट्ट, राजमा इत्यादि पर्वतीय दालों तथा सामान्य दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन हेतु प्रयासरत है।
- पर्वतीय क्षेत्रों के स्थानीय फसलों के बीजों पर तीन चौथाई अनुदान एवं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के विपणन पर दस प्रतिशत बोनस दिया जा रहा है।
- स्थानीय फसल उत्पादों का विपणन, विपणन बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है।
- पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि यंत्रो पर नब्बे प्रतिशत तक अनुदान की व्यवस्था है।
- जैविक मण्डुआ उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जैविक उत्पाद परिषद् का सुदृढ़ीकरण की योजना के कार्यक्रमों को विस्तार दिया जा रहा है।
- गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार तथा उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन के लिए कटिबद्ध है।
- मॉडीफाइड राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संचालित की जा रही है।
- जैविक कृषि में संतृप्तीकरण हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जनपद पौड़ी के श्रीनगर क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।
- सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत धान, गेहूँ, दाल एवं विभिन्न फसलों के उत्पादन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(2) **मेरी सरकार बागवानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन** का कार्य योजनाबद्ध रीति से कर रही है।

- सरकार रोपण सामग्री का उत्पादन, फल पौध रोपण की योजना, मशरूम उत्पादन, उद्यान कार्ड वितरण, मौन पालन योजना, घेरबाड़ योजना, फसल बीमा योजना, उद्यानों की जीर्णोद्धार की योजना, बोरबैल विकास की योजना, मुख्यमंत्री संरक्षित खेती योजना, ग्रीन हाउस की पॉलीथीन बदलाव की योजना का क्रियान्वयन कर रही है।
- राज्य में जड़ी–बूटी उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहनरी (अल्मोड़ा), देघाट (अल्मोड़ा), पौड़ी (जैयरीखाल, पौड़ी) तथा जोशीमठ (चमोली) में 04 क्लस्टर

स्थापित किये गये हैं। इन क्लस्टरों के माध्यम से दालचीनी, बुल्गेरियन रोज, तिमूर एवं लेमनग्रास की खेती तथा विपणन किया जायेगा।

- सरकार जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों हेतु गतिविधियों के संचालन एवं प्रसारण करने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में जैव प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है जो शीघ्र अस्तित्व में आ जायेगा। सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर विधि द्वारा कीवी फल, ब्राहमी एवं आरकिड के उत्पादन हेतु शोध कर प्रोटोकाल तैयार कर रही है।
- सरकार ने भविष्य में परिषद् द्वारा ऊतक संवर्धन विधि द्वारा अखरोट, सेब, केसर, खुमानी, चेरी, आदि में पौधों को टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रोटोकाल के बाद इनका भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जायेगा जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रहकर खेती करने वाले किसानों को आजीविका एवं रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- जैवप्रौद्योगिक तकनीकों पर आधारित बायोफर्टिलाइजर, वर्मी कम्पोस्ट, वर्मी वास द्वारा चुनिन्दा केन्द्रों पर तकनीकी स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(3) **मेरी सरकार गन्ना किसानों के प्रति भी संवेदनशील है और गन्ना मूल्य घोषित करने के** अतिरिक्त गन्ना कृषकों को प्रशिक्षण, बीज, उर्वरक इत्यादि उपलब्ध करा रही है।

(4) **सहकारी सहभागिता योजना में सरकार कृषकों को ब्याज पर अनुदान सहित ऋण की** उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है।

- राज्य में उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना किये जाने के दृष्टिगत एवं उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत करते हुए अपर मुख्य सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन किया गया है।
- राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के द्वारा अपने जमाकर्ताओं हेतु रुपे डेबिट कार्ड योजना प्रारम्भ की गई है।
- राज्य सहकारी बैंक द्वारा हल्द्वानी एवं देहरादून में जमाकर्ताओं हेतु ए0टी0 एम0 सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

(5) **राज्य में पशुपालन लोगों की आजीविका का प्रमुख व्यवसाय है। इस का मूल उद्देश्य** प्रदेश में उपलब्ध पशुधन को उन्नतशील बनाना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कराना तथा पशुओं की संख्या एवं दुग्ध उत्पादन क्षमता को परिवर्द्धित कर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों का संचालन किया है:-

- अभिनव पहल के रूप में पशुपालकों के आजीविका संवर्द्धन हेतु अहिल्याबाई होल्कर भेड़/बकरी विकास योजना का संचालन।
- चारे की पूर्ति हेतु राज्य के पर्वतीय जनपदों की वन पंचायतों में भारत सरकार की ग्रासलैण्ड डेवलपमेन्ट एवं ग्रास रिजर्व योजना के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता से बहुवर्षीय चारा पौधों का रोपण कर चारागाह विकसित किये जा रहे हैं। सभी विकासखण्डों में चारा बैंकों की स्थापना कर "काम्पैक्ट फीड ब्लॉक एवं चाटन भेली" पशुपालकों को उपलब्ध कराये गये हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गो के आर्थिक उत्थान हेतु प्रोत्साहन के रूप में कुक्कुट इकाइयों की स्थापना हेतु पचास-पचास कुक्कुट चूजे निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
- राज्य में गाय एवं भैंसों की नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुदूर ग्रामीण अंचलों तक कृत्रिम गर्भाधान कार्य को विस्तारित करने के साथ-साथ नये केन्द्रों की स्थापना की गयी है। पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में एक भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला स्थापित की गई है, जिसमें इस तकनीक द्वारा लगभग डेढ़ सौ नवज़ात उच्च नस्ल की संतति उत्पन्न की गयी है।
- पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पशुधन बीमा योजना, भेड़ पालको की सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय भेड़पालक समूह बीमा योजना संचालित की गयी है ।
- पशुपालको को निःशुल्क चारा बीज उपलब्ध कराने हेतु फॉडर प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन योजना का क्रियान्यवन शीघ्रता से किया जायेगा।
- दुग्ध उत्पादकों को समितियों से जोड़ने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन एवं अन्य योजनायें संचालित की जा रही हैं। गंगा गाय महिला डेयरी

योजना के अन्तर्गत अनुदान देय है तथा इसके अन्तर्गत तीन वर्षों में लगभग 10 हजार पशु क्रय करने का लक्ष्य है। अब तक 1400 से अधिक उन्नत नस्ल की गायें क्रय कर वितरित की गई हैं। जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा दैनिक तरल दुग्ध बिक्री को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- सरकार दुग्ध उत्पादन के साथ–साथ अण्डा उत्पादन, ऊन उत्पादन पर कार्य कर रही है और उसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं तथा मत्स्य पालन की वृद्धि के लिए निरन्तर प्रयासरत है और डेयरी विकास के लिए वचनबद्ध है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्थानीय नस्ल की बद्री गायों के सम्वर्द्धन हेतु जनपद चम्पावत के नरियालगांव में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गयी है।
- भारत सरकार द्वारा सहायतित एस्केड योजना से राज्य में पशुधन की सुरक्षा हेतु टीकाकरण कार्य किया जा रहा है एवं भारत सरकार की स्वीकृति से राज्य में जूनोटिक रोगब्रूसेलोसिस नियंत्रण हेतु सक्रिय सर्विलांस कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(6) **सरकार पर्यावरण, वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में** हमने निम्नांकित महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं:–

- नवीनतम बाघ गणना के अनुसार सर्वाधिक बाघ विद्यमान होने वाले राज्यों में उत्तराखण्ड देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है।
- उत्तराखण्ड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त कर लिया गया है। इस कार्ययोजना में राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की रणनीति तैयार कर ली गयी है।
- सरकार एक ओर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये निर्देशों का सम्मान एवं दी गयी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है तो दूसरी ओर अपने राज्य की विकास की आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु भी संकल्पबद्ध है। अतः मेरी सरकार इन दोनों के बीच संतुलन बनायेगी साथ ही नमामि गंगे अभियान एवं गंगा स्वच्छता से सम्बन्धित कार्यों में राज्य सरकार यथा सम्भव सहयोग प्रदान करेगी।
- मेरी सरकार द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड आयोजित कराकर प्रकरणों का परीक्षण करके नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को प्रेषित की जा रही है। नोडल आफिसर के माध्यम से वन संरक्षण के अन्तर्गत अनापत्तियों का ससमय निस्तारण किया जा रहा है

ताकि विकास प्रक्रिया में विलम्ब न हो। आपदा पुनर्निर्माण कार्यों के अन्तर्गत 5.0 हेक्टेयर तक की छूट की समय सीमा अक्टूबर, 2016 तक बढ़ायी गयी है।

- उत्तराखण्ड में वनों पर निर्भरता कम करने तथा स्थानीय लोगों की प्रकाश, ईंधन व चारा की मॉग की पूर्ति हेतु निजी भूमियों पर ईंधन, चारापत्ती, फलदार व प्रकाष्ठ प्रजातियों के रोपण को प्रोत्साहन देने हेतु मुख्यमंत्री की "फ्लैगशिप" योजना "हमारा पेड़ हमारा धन योजना" गत वर्ष से प्रारम्भ की गयी है।
- मुख्यमंत्री की "फ्लैगशिप" योजना "वर्षा जल संरक्षण योजना" के अन्तर्गत वर्ष कैम्पा में भू–जल की उपलब्धता में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु जल संरक्षण संरचनाओं यथा जलकुण्डों का निर्माण, जलकुण्डों व जलस्रोतों का पुनरोद्धार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मृदा एवं जल संरक्षण के अन्तर्गत छोटे–छोटे नदी नालों में चैकडैम का निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। इससे समुचित जल व मृदा का संरक्षण होगा।
- मानव वन्यजीव संघर्ष के अधीन जान–माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु इस वर्ष अब तक लगभग आठ करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है। इससे निःसन्देह स्थानीय लोगों में वन्यजीवों के प्रति रोष में कमी आई है।
- हल्द्वानी में एक उच्च स्तरीय चिडियाघर बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- मालसी डियर पार्क का उच्चीकरण कर जू में परिवर्तन किया जा रहा है।

(7) **मेरी सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के असिंचित क्षेत्रों को** सिंचाई सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए प्रयासरत है। आबादी एवं कृषि भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा बाढ़ प्रबन्धन परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

- कालागढ़ स्थित सिंचाई विभाग के राज्य अभियन्त्रण अकादमी तथा रुड़की स्थित भारतीय अनुसन्धान संस्थान को मिलाकर सेण्टर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इससे सिंचाई के क्षेत्र में उन्नत तकनीकों का लाभ प्रदेश को प्राप्त होगा।
- जनपद बागेश्वर के बैजनाथ बैराज का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जनपद अल्मोडा में पेयजल हेतु कोसी बैराज का निर्माण तथा जनपद नैनीताल के रामनगर में कोसी बैराज पुनरोद्धार का कार्य प्रगति पर है।

- आने वाले समय में जल संकट की आशंका के दृष्टिगत "उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जलकर अधिनियम, 2012" तथा "उत्तराखण्ड जल प्रबन्धक एवं नियामक अधिनियम", 2013, दोनों अधिनियमों की संगत धाराओं में संशोधन करते हुए एक ही उत्तराखण्ड जल संसाधन प्रबन्धन और नियामक आयोग का गठन किया जाना प्रस्तावित है ताकि जनसामान्य को स्वच्छ पेयजल उपलब्धता, जल संसाधनों एवं स्रोतों के प्रबन्धन तथा भूगर्भ जल, गाड़, गधेरे, झरने व तालाब इत्यादि जल का संरक्षण, विनियम सहित जल के वाणिज्यिक उपयोग पर उपभोगकर/रॉयल्टी वसूल की जा सके तथा उसके अनावश्यक एवं अनियन्त्रित दोहन को नियन्त्रित किया जा सके।

(8) सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा विशेष तौर पर पर्वतीय/ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने के प्रति दृढ़ संकल्प है। इस उद्देश्य से महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, ग्रामीण आवास योजना (इन्दिरा आवास योजना), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.), दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना, राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना, उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि, इन्दिरा अम्मा भोजनालय, मेरा गाँव मेरी सड़क योजना का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त स्रोतों के संवर्द्धन हेतु ग्राम्य तालाब विकास विभाग का गठन किया गया है।

- मेरी सरकार ने सड़क मार्ग से अछूते प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो अभी तक किसी भी योजनान्तर्गत सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं को सड़क मार्ग से जोड़ने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना "मेरा गाँव मेरी सड़क" प्रारम्भ की गयी है। इस योजना से गाँव की पैदावार के विपणन में सुगमता होगी तथा पलायन रोकने में मदद मिलेगी। राज्य में ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विभाग का सृजन किया गया है।
- इस प्रयोजन हेतु निजी भूमि, सिविल सोयम एवं वन भूमि का अधिग्रहण कर शासनादेश जारी किये जा चुके हैं। इस क्रम में मेरी सरकार ने योजना के प्रथम चरण में प्रति विकासखण्ड एक योजना का चयन किया और इस हेतु पर्याप्त धनराशि भी अवमुक्त की गयी है। इनमें से कुछ योजनाओं पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ किया गया है।

- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है।
- मेरा गाँव मेरा तालाब योजना के अन्तर्गत जलाशयों का निर्माण प्रगति पर है।

(9) **मेरी सरकार भवन विहीन पंचायतों में भवनों का निर्माण करा रही है।** क्षमता विकास हेतु त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कर रही है। इसके अतिरिक्तः–

- पच्चीस लाख प्रति विकास खण्ड की दर से क्षेत्र पंचायत विकास निधि स्थापित की गयी है।
- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान को प्राथमिकता से संचालित किया जा रहा है।
- पंचायत सशक्तिकरण एवं जबावदेही प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार योजना संचालित की गयी है।
- ई–पंचायत कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पी0इ0एस0 साइट के 11 सॉफ्टवेयरों में से लगभग सभी सॉफ्टवेयरों पर अभिलेखों का रखरखाव राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ।
- जिला हरिद्वार में पंचायत चुनावों को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराया गया है।

(10) **मेरी सरकार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों** में चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है।

- सरकार ने ₹ पन्द्रह हजार प्रति वर्ष के शिक्षण शुल्क पर एक सौ डाक्टरों की सीटें मेडिकल कॉलेज में निर्धारित की हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षित चिकित्सकों को राज्य के दुर्गम/अतिदुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में न्यूनतम तीन वर्ष की राजकीय सेवा दिया जाना अनिवार्य किया है।
- चिकित्सकीय सुविधाओं को जनमानस की वित्तीय एवं भौतिक पहुँच में उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड फारेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट, हल्द्वानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की एक सौ सीटें एवं एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम की कुल 39 सीटें उपलब्ध हैं, जिनसे प्रतिवर्ष एक सौ उन्तालिस चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो रहे हैं।

- मेरी सरकार ने स्वास्थ्य–सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार व रूद्रपुर में कुल 05 नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का संकल्प लिया है। वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज दून को इसी शैक्षिक सत्र से क्रियाशील करने हेतु सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
- नये मेडिकल कॉलेज में भूमि चयन/निर्माण कार्य आदि की गतिविधियाँ भी प्रारम्भ की जा चुकी हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ को बाबू जगजीवन राम एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार को डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम से संज्ञानित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- आमजन को परा–चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार जी0एन0एम0 स्कूलों का संचालन कर रही है और इनमें लगातार सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थाएँ की गयी हैं। आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिये सरकार निरन्तर प्रयासरत है, जिससे राज्य के सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ तथा दुष्परिणाम रहित चिकित्सा प्राप्त हो सके। इस क्रम में:–
- 04 नवीन आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना की गयी है।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन में सम्पूर्ण सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- प्राकृतिक/दैवीय आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुये ग्रामीण एवं दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में जन सामान्य को प्राथमिक स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की है।
- राजकीय कर्मचारियों/पेंशन धारकों तथा आयकर दाताओं को छोड़कर आम जनता को कैश–लैश चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करने हेतु गत अप्रैल माह से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्तमान तक 8 लाख कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं और शेष कार्ड बनाने की कार्यवाही गतिमान है।
- सभी चिकित्सा इकाईयों को सरकारी भवन में क्रियाशील करने हेतु कृत संकल्प है। जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत महिला बेस चिकित्सालय सोमेश्वर, जनपद चमोली के अन्तर्गत बेस चिकित्सालय गोपेश्वर जनपद बागेश्वर में बेस चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली में एक सौ शैय्यायुक्त बेस चिकित्सालय, जनपद पिथौरागढ़ में

नवचयनित स्थल ग्राम ल्यून्ठूड़ा में बेस चिकित्सालय जनपद देहरादून के विकासखण्ड चकराता के स्थान त्यूनी में एक सौ शैय्यायुक्त चिकित्सालय की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार को बेस चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत किये जाने एवं भवन निर्माण हेतु वित्त का प्राविधान किया गया है।

- पिथौरागढ, अल्मोडा, पौडी, टिहरी तथा चमोली में बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज निर्माण प्रारम्भ।

(11) मेरी सरकार राज्य में विद्यालयी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापरक शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

- सरकार शिक्षक विहीन विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए शिक्षकों का चयन कर रही है। प्राइमरी से परास्नातक तक अब शिक्षकों की नियुक्ति अधिकांशतः हो चुकी है। प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के 515 पदों पर पदोन्नति की गयी है। शीघ्र ही शेष विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों को पदोन्नति से भरा जायेगा।
- मेरी सरकार ने प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा के अर्न्तगत 500 आदर्श विद्यालय जिसमें 50 विद्यालय नगरीय क्षेत्र में तथा प्रत्येक विकासखण्ड में 5–5 आदर्श विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं।
- माध्यमिक शिक्षा में तात्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत 6126 गेस्ट टीचरों की भर्ती की गयी है। लोक सेवा आयोग, प्राविधिक शिक्षा परिषद् तथा पदोन्नति से कुल 5733 एल0टी0 एवं प्रवक्ता के पदों की चयन प्रक्रिया गतिमान है।
- मेरा गाँव तथा मेरा धन योजना के अन्तर्गत स्थानीय व्यक्तियों को विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- विद्यालयों का उच्चीकरण, राजीव गाँधी अभिनव विद्यालयों की स्थापना, नये विद्यालयी भवनों का निर्माण, पुराने विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जा रहा है। इस

प्रयोजन हेतु निजी सेक्टर का सहयोग लिया जायेगा ताकि निजी सेक्टर की दक्षता का लाभ प्राप्त हो सके तथा सरकार के वित्तीय भार में कमी आये।

- सरकार ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों को आम जनों की माँग पर विभिन्न विषयों में मान्यता देने, अनुदान सूची में सम्मिलित करने तथा पदों को सृजित करने का कार्य किया है, जिससे अध्ययन/अध्यापन में कोई कठिनाई न हो।
- "जन–जन का प्रयास शिक्षा का विकास कार्यक्रम" आयोजित कर प्रत्येक बच्चे को स्कूल तक लाने में अग्रणी भूमिका निभा रही है।
- प्रदेश के 731 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के विद्यार्थियों में क्रियात्मक अंग्रेजी एवं सॉफ्ट स्किल विकसित करने हेतु उन्नति कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अभूतपूर्व परिणाम दृष्टिगत हुए हैं।
- संस्कृत शिक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करते हुए माध्यमिक स्तर और उच्च शिक्षा स्तर पर नित नये क्रिया–कलापों का संचालन किया है ताकि राज्य में द्वितीय भाषा का दर्जा प्राप्त संस्कृत को गति प्रदान की जा सके।
- सरकार संस्कृत के संरक्षण, संवर्द्धन और उन्नयन के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में उसके सभी पहलुओं पर सरकार कार्य कर रही है।
- बेरोजगारी को दूर करने के दृष्टिगत सरकार पाठ्यचर्या विकास एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा डिप्लोमा तकनीकी संस्थानों में प्रवेश क्षमता को बढ़ाकर पिछड़े क्षेत्रों को भी तकनीकी शिक्षा से जोड़ रही है।
- सरकार राज्य के अति पिछड़े क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ करने पर बल दे रही है। इस दिशा में मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया जा रहा है।
- सरकार के विजन 2020 के अनुरूप राज्य में उत्कृष्ट वैज्ञानिक मानव संसाधन विकसित करने हेतु विज्ञान धाम परियोजना अन्तर्गत क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है, जो शीघ्र आम जनमानस हेतु उपलब्ध करा दिया जायेगा। विज्ञान केन्द्र में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, कोलकाता द्वारा वैज्ञानिक मॉडल्स स्थापित कराये जा रहे हैं जो राज्य का वैज्ञानिक, शिक्षा एवं पर्यटन हब बनेगा।

- दशम् उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काँग्रेस का आयोजन, उत्तराखण्ड साइन्स एन्क्लेव का आयोजन, जनपद अल्मोड़ा में उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना, विज्ञान धाम में तारामण्डल का निर्माण कराया गया है।
- परिषद् द्वारा पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, देहरादून के साथ संयुक्त रूप से सौर एवं पवन ऊर्जा पर परियोजना तैयार कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को भेजी गयी थी जिस पर प्रस्तुतिकरण दिया जा चुका है।
- आर0बी0एफ0 परियोजना के अन्तर्गत मैनुअल व प्रशिक्षण की परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् भेजा गया है।
- प्रदेश के दुर्गम–दूरस्थ क्षेत्रों तक उच्च शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विगत समय में कई नये महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं। जहाँ राज्य गठन के समय प्रदेश में 35 राजकीय महाविद्यालय संचालित थे, वहाँ वर्तमान में कुल 94 राजकीय महाविद्यालय हैं। मेरी सरकार इन महाविद्यालयों के भवन निर्माण सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करेगी।
- भारत सरकार के सहयोग से संचालित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत अधिक से अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- उच्च शिक्षा के विस्तार, गुणवत्ता एवं दक्षता के उन्नयन की दृष्टि से निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- राज्य के छात्र–छात्राओं को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रोजेक्ट उत्कर्ष नामक योजना संचालित की गई है।
- शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रेगुलेशन, 2009 में निर्धारित शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता अनुसार चयन प्रक्रिया अपनाई गयी है। वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय में शिक्षण कार्य के विधिवत संचालन के दृष्टिगत शिक्षकों के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से नियमित चयन तक गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से संविदा शिक्षक तैनात कर दिये गये हैं। मेरी सरकार यथाशीघ्र नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही करेगी।

- प्रदेश में उच्च शिक्षा सुविधा पहुँच की स्थिति देश के अन्य कतिपय राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत ठीक है, जो कि राज्य की जी0ई0आर0 (सकल नामांकन दर) 27 से परिलक्षित होती है, जबकि भारत सरकार में इसका औसत दर 22 है।
- मेरी सरकार विधि शिक्षा को बढावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में अग्रेत्तर कार्यवाही करेगी, जिससे आगामी वर्ष में कक्षाएँ संचालित हो सके। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में स्थापित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी।
- सरकार कुमाऊँनी एवं गढ़वाली बोली की भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ लोकल लैंगवेज स्थापित किये जाने हेतु दून विश्वविद्यालय एवं कुमाऊँ विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर को विकसित किये जाने की योजना पर विचार करेगी। साथ ही मेरी सरकार कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कैंसर रिसर्च सेण्टर की स्थापना करने का प्रयास करेगी।
- जहाँ नियमित आधार पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने में किसी युवा को समयाभाव या अन्य कारण से कठिनाई है वहाँ मेरी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से पहुँच सुनिश्चित कर रही है।

(12) आपदा की दृष्टि से हमारा प्रदेश अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र है। भूकम्प, अतिवृष्टि, भू–स्खलन से जन–धन की अपार क्षति होती रही है। मौसम के सटीक पूर्वानुमान/अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक सहायतित क्षमता विकास कार्यक्रम पी0आई0यू0 द्वारा 64 स्वचालित मौसम केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है। जिनमें से 04 स्थापित किये जा चुके हैं। 02 डॉप्लर वैदर रडार की स्थापना की जा रही है। राज्य में आपदा की स्थिति में यात्रियों एवं स्थानीय निवासियों को आश्रय प्रदान करने तथा त्वरित निकासी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेल्टर–कम–गोदामों तथा 60 हैलीपेडों का निर्माण किया जा रहा है। 2013 की आपदा से क्षतिग्रस्त आवासों से सम्बन्धित परिवारों को विश्व बैंक पोषित सुरक्षित भवन परियोजना के अन्तर्गत नये आवास तैयार करके उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

- वर्ष 2013 के जून माह में गठित प्राकृतिक विभीषिका से क्षतिग्रस्त केदार पुरी मन्दिर क्षेत्र में अब तक किये गये बाढ़ सुरक्षा, पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के कार्य सराहनीय रहे हैं। अभी भी पुनर्निर्माण कार्य गतिमान है।

- राज्य में आपदा प्रबन्धन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर आधारित अध्ययन हेतु "आपदा प्रबंधन सैल" का गठन किया है। इसके अधीन राष्ट्रीय स्तर पर संचालित इमरजेन्सी मैनेजमेन्ट फॉर डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्रोग्राम को राज्य स्तर पर संचालित करने हेतु राज्य में डिजिटल वालिन्यटियर्स तैयार कर रही है।

- यू–सैक द्वारा वेब बेस्ड सिटी इंफोर्मेशन सिस्टम सृजित किये जा रहे हैं जिसमें शहरों/नगरों से संबंधित समस्त जानकारी– शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवायें, सरकारी कार्यालयों इत्यादि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

- यमुना बेसिन में स्थित हिमनदों का सैटेलाइट डेटा के उपयोग से अनुश्रवण किया गया तथा सत्रह जलागम क्षेत्रों में वाटरशेड प्राईवेटाइजेशन हेतु कार्य योजना तैयार की गई है।

- मेरी सरकार ने यू–सार्क द्वारा राज्य में छात्रों, युवाओं एवं जनसामान्य तक विज्ञान शिक्षा के प्रसार हेतु प्रौद्योगिकी संवर्द्धित विज्ञान शिक्षा का प्रसार उत्तराखण्ड के सूदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुँचाने के लक्ष्य के अनुरूप कार्य प्रारम्भ किया है।

(13) **सरकार शहरों के नियोजित विकास हेतु कटिबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में** जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए सरकार द्वारा निर्माण से सम्बन्धित बायलॉज में परिवर्तन करके भवनों की ऊँचाई आदि में शिथिलताप्रदान की गई है ताकि आवासीय अनावासीय भवन, पार्किंग इत्यादि समस्याओं का सम्यक् समाधान हो सके। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि विशेष रूप से बिना नक्शा पास किए एकल आवासीय भवनों के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में वन टाईम सेटलमेंट योजना लागू की गयी है, जिससे लगभग तीन हजार लोग लाभान्वित हुए।

- ग्रामीण बसावटें तेजी से शहरों का रूप धारण कर रही हैं उत्तराखण्ड भी इससे अछूता नही है। इन बसावटों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर पंचायतों का गठन किया गया है तथा कुछ नगर पंचायतों को नगरपालिकाओं में परिवर्तित किया गया है।

- सरकार लघु एवं मध्यम दर्जे के नगरों के विकास पर भी विशेष बल दे रही है। इसके अन्तर्गत 23 लघु स्मार्ट कस्बे विकसित किये जायेंगे। इस उद्देश्य से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जा चुकी है इसकी दो इकाईयां रूद्रपुर और देहरादून में सृजित की गई हैं। स्मार्ट कस्बों के सृजन हेतु एक पृथक से निगम की स्थापना भी प्रस्तावित है।
- सरकार बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की स्थापना करने जा रही है। यात्रियों को त्वरित, मितव्ययी एवं सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के साथ मुराद नगर से हरिद्वार तक मेट्रो रेल लाईन निर्माण के सम्बन्ध में हुई सहमति के क्रम में सरकार अग्रेत्तर कार्यवाही करेगी।
- सरकार जसपुर–काशीपुर–रूद्रपुर–किच्छा–नानकमत्ता–सितारगंज–खटीमा–बनबसा–टनकपुर परिक्षेत्र तथा रामनगर–कालाढूंगी–हल्द्वानी–काठगोदाम परिक्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु अध्ययन करायेगी ताकि इन्हें नगरीय सर्किट के तौर पर विकसित किया जा सके और यहाँ सम्यक् नगरीय सुविधाएं सृजित की जा सकें।
- गैरसैंण विकास परिषद् का गठन किया गया तथा इस क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करते हुए विकास के लिए विशेष प्रयास किए गये, स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सबके लिए आवास योजना बनायी जा रही है।
- विकास प्राधिकरण देहरादून में ई0डब्लू0एस0, एल0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0 भवनों का निर्माण कई वर्षों बाद प्रारम्भ किया गया तथा लाटरी द्वारा आवंटन किया गया।
- मेरी सरकार रिवर फ्रंट का कार्य प्रारम्भ कर रही है। इस हेतु प्रथम चरण में नब्बे करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है।
- स्मार्ट सिटी योजना पर भारत सरकार की सहमति उपरान्त कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ करेगी।
- यातायात को सुगम बनाये जाने हेतु आवश्यकतानुसार फुट ओवर ब्रिज का निर्माण करायेगी।
- पर्किंग की समस्या के निराकरण हेतु एस्ले हॉल में मल्टीलेबल पार्किंग तथा एम0डी0डी0ए0 द्वारा जिला देहरादून में पी0आर0टी0 योजना प्रस्तावित है।

- सरकार जे0एन0एन0यू0आर0एम0, राजीव आवास, स्वच्छ भारत मिशन, ए0डी0बी0 सहायतित योजनाओं, नगरीय अवस्थापना सुविधा, नगर निकायों में पार्क की स्थापना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि पर भी विशेष ध्यान दे रही है ताकि आम जनता को इसका समुचित लाभ मिल सके।

(14) **हमारे देश एवं प्रदेश की धर्मपरायण जनता की भावना, आस्था एवं विश्वास को ध्यान** में रखते हुए मेरी सरकार ने हरिद्वार अर्द्धकुम्भ, 2016 के आयोजन हेतु समयबद्ध कार्य पूर्व में ही प्रारम्भ कर दिये थे। नीति आयोग, द्वारा अर्द्धकुम्भ–2016 हेतु ₹ 166.67 करोड़ की संस्तुति के बावजूद अब तक भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नही हुई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रत्येक कुम्भ/अर्द्धकुम्भ के आयोजन हेतु धनावटंन किया जाता रहा है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्ति की प्रत्याशा में हमने अब तक ₹ तीन सौ इक्कीस करोड़ के स्थायी एवं अस्थायी निर्माण कार्य सम्पन्न किये हैं। अर्द्धकुम्भ के दो स्नान भी निर्विघ्न एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं।

(15) सड़क, पुल एवं परिवहन

- राज्य में चार हजार से अधिक ग्राम अभी भी सड़क मार्गो से जोड़े जाने हैं। इनमें से दो हजार आठ सौ ग्रामों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्ग स्वीकृत किये जा चुके हैं। अवशेष ग्रामों के लिए स्वीकृति के भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। यथासम्भव सुरंगों के निर्माण द्वारा सड़कों की लम्बाई घटाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि प्रत्येक मौसम में यातायात की सुविधा बनी रहे।
- टिहरी बाँध के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु डोबरा चाँटी पुल का निर्माण प्रगति पर है जिससे प्रताप नगर क्षेत्र की जिला मुख्यालय टिहरी से सड़क मार्ग से दूरी कम होगी। श्रीनगर (गढ़वाल) में चौरास पुल का निर्माण भी प्रस्तावित है।
- पर्वतीय भू–भाग की बहुलता, पर्वतों के तीखे ढाल, पारिस्थितिकी संवेदनशीलता एवं घने वनों के कारण सुरंग, रोप–वे एवं पुलों का निर्माण राज्य के लिए अत्यावश्यक है। इनके निर्माण हेतु अति उन्नत तकनीकी की आवश्यकता है। इन परियोजनाओं के विकास हेतु वर्तमान में हम राज्य से बाहर की संस्थाओं पर निर्भर हैं। ऐसी स्थिति में

राज्य की अपनी संस्था बनाने की आवश्यकता है। अतः सरकार राज्य में ब्रिजेज, रोपवेज एण्ड टनल निगम की स्थापना करने जा रही है।

- जनपद टिहरी में मुनि की रेती नामक स्थान पर कैलाश गेट के समीप गंगा नदी के ऊपर तीन सौ दस मीटर लम्बे स्पान के सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत जनपद देहरादून में डाट काली मन्दिर में तीन सौ पचास मी० लम्बी सुरंग, मोहकमपुर में आर०ओ०बी०, हरिद्वार बाईपास पर आर०ओ०बी० का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
- कोसी नदी पर पी०पी०पी० मोड के अन्तर्गत रामनगर में तीन सौ साठ मी० लम्बा पुल एवं पाँच छोटे सेतु का निर्माण कार्य, चौखुटिया–मासी तेरह किमी० एवं भतरोजखान–भिकियासैंण सत्रह किमी० सिंगल लेन सड़क का डेढ़ लेन में निर्माण कार्य, नैनीताल बाईपास लम्बाई लगभग सात किमी०, दो वृहद सेतु का निर्माण कार्य, अल्मोड़ा शहर के दो भागों को जोड़ने हेतु सुरंग का कार्य, हल्द्वानी शहर के अन्तर्गत नहर को कवर कर सड़क चौड़ीकरण तथा शहर की सड़कों के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर है।
- राज्य के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों तक यातायात को सुगम बनाने के लिए एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से रोप–वे निर्माण को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
- सरकार इस वित्तीय वर्ष में राज्य में आठ सौ छियालिस किलोमीटर के आठ राज्याधीन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने हेतु कार्यवाही करेगी। इसके अतिरिक्त चार धाम मार्गों के उच्चीकरण की भी व्यवस्था की जा रही है।
- देहरादून, ऋषिकेश तथा हरिद्वार में मैट्रो रेल हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- टनकपुर–जौलजीवी मोटर मार्ग के शीघ्र निर्माण हेतु भारत सरकार से सतत् अनुश्रवण किया गया और प्रस्तावित पंचेश्वर बाँध के कारण मार्ग की डी०पी०आर० भारत सरकार द्वारा लम्बित रखे जाने को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा फिलहाल पंचेश्वर बाँध के निर्माण स्थल तक की डी०पी०आर० स्वीकृत किये जाने पर ठुलीगाड़ से रूपालीगाड़ तक 43 किमी० मार्ग हेतु ₹ 274.70 करोड़ की पुनरीक्षित डी०पी०आर० भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दी गयी है।

- 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सरकार द्वारा परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करा रही है।
- चालक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी के निर्माण हेतु सरकार कटिबद्ध है। इस हेतु भूमि पर भारत सरकार की अनापत्ति प्राप्त हो गयी है। सरकार इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही कर रही है।

(16) **राज्य में हवाई पट्टियों एवं हैलीपैड को सुदृढ़ करने के प्रयास किये जा रहे हैं।** चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी), नैनी सैनी (पिथौरागढ़), से हवाई सेवाएं प्रारम्भ करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सहस्त्रधारा हैलीपैड से श्रीनगर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ, औली तथा काशीपुर, हल्द्वानी से मुन्स्यारी हैलीकॉप्टर सेवा को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि प्रमुख पर्यटक एवं धार्मिक स्थल आपस में जुड़ सके। राज्य में हिमालय दर्शन योजना की लोकप्रियता को देखते हुए इसका विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

(17) **सरकार बिजली की खपत कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस ओर ध्यान देते** हुए घरेलू उपभोक्ताओं को एल0ई0डी0 बल्ब उपलब्ध करा रही है।

- राष्ट्रीय महत्व की किसाऊ बहुउद्देश्यी परियोजना (छः सौ साठ मेगावाट) पर हिमाचल प्रदेश के साथ एम. ओ. यू. के बाद की कार्यवाही गतिमान।
- सरकार ने नवीन एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय/उत्तराखण्ड गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास अभिकरण की रुफटॉप नीति के अन्तर्गत निगम के पथरी जल विद्युत गृह पर पाँच सौ किलोवाट के सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना की है।
- यूजेवीएन लिमिटेड के मुख्यालय 'उज्ज्वल' में एक सौ किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट का लोकार्पण किया गया।
- सरकार की सूक्ष्म एवं लघु जल विद्युत नीति के क्रियान्वयन में दो मेगावाट तक की परियोजनाओं में पंचायतीराज संस्थाओं की भागीदारी, निर्माण, संचालन एवं रखरखाव हेतु यूजेवीएन लिमिटेड के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ।

(18) **मेरी सरकार राज्य में रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने एवं पलायन को रोकने के** उद्देश्य से वृहद उद्योगों के साथ–साथ हस्तशिल्प एवं लघु उद्योगों के संवर्द्धन हेतु प्रयासरत है।

- मेरी सरकार औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। पंतनगर में सिडकुल कॉनकोर इन्फ्रा लि० (जे०वी०) द्वारा ₹ अट्ठानवे करोड़ लागत से लॉजिस्टक हब का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। इस लॉजिस्टक हब के निर्माण से उद्योगों के कच्चे माल एवं तैयार माल के ढुलान के व्यय में कटौती होगी।

- औद्योगिक आस्थान पन्तनगर के अन्तर्गत कल्याणी नदी का चैनेलाईज़ेशन करते हुए लगभग 16 एकड़ भूमि में सिटी पार्क बनाते हुए पचास एकड़ रिकलेम्ड भूमि पर उद्योग लगाने हेतु प्रयोग में लाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

- शासन द्वारा टैक्सटाईल पॉलिसी की स्वीकृति के पश्चात् काशीपुर एवं जसपुर में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु प्रक्रिया गतिमान हैं। साथ ही सितारगंज फेज–दो में एक सौ पचास एकड़ भूमि टैक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु चिन्हित कर दी गई है। जिस हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है।

- ऐस्कोर्ट फार्म में लगभग दो सौ एकड़ भूमि आई०आई०एम० को आंवटित कर दी गई है। शेष लगभग तीन सौ एकड़ भूमि पर नॉलेज हब/प्रदूषण रहित उद्योग विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

- मारचुला, ग्राम कुप्पी, अल्मोड़ा में लगभग बारह हेक्टेयर भूमि पर पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। जिसमें अवस्थापना विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

- मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों/काश्तकारों हेतु मिनी औद्योगिक आस्थान विकसित कर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं, इस के अन्तर्गत पुरोला, सरोठ, मुन्स्यारी, भिकियासैंण एवं बेतालघाट में मिनी औद्योगिक आस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है।

- टिहरी गढ़वाल मदन नेगी में जाइका एवं सिडकुल के संयुक्त प्रयास से ईको टूरिज्म परिस्थितियों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

- स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट के आई0आई0ई0 हरिद्वार में प्रायोगिक तौर में क्रियान्वयन के पश्चात् अन्य औद्योगिक आस्थानों में स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट का क्रियान्वयन कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत उद्यमियों की सुविधा हेतु भूमि आवंटन हेतु आवेदन ऑनलाइन भरे जाने की एवं सिडकुल के शुल्कों को ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है।

- भविष्य में राज्य में निवेश लाने हेतु नेपा, खुरपिया की भूमि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। इन नये आस्थानों को जहाँ एक ओर सिडकुल कॉनकोर के संयुक्त उपक्रम द्वारा पन्तनगर में स्थापित लॉजिस्टक हब का लाभ मिलेगा वहीं दूसरी ओर भारत सरकार की ए0के0आई0सी0 कोरीडोर योजना के लाभ भी मिलेंगे।

- राज्य सरकार, राज्य की स्टार्ट अप योजना बनाते हुए राज्य के नौजवानों को आमदनी बढ़ाने हेतु सुअवसर देने के लिये कटिबद्ध है, जिससे कि नौजवानों को नयी योजनायें बनाकर राज्य की विकास दर में भागीदार बनाया जा सके।

- सरकार ने नई एमएसएमई नीति लागू की है, जिसके अन्तर्गत राज्य को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरुप विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन यथाः पूँजी निवेश उपादान, ब्याज उपादान, वैट प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट, विद्युत बिल व परिवहन लागत प्रतिपूर्ति एवं अन्य संस्थागत सुविधाओं, अवसंरचनात्मक सहयोग एवं सुगमता विनियमन व सरलीकरण आदि महत्वपूर्ण प्राविधान किये गये हैं।

- मेरी सरकार प्रदेश की महिलाओं के रोजगार एवं स्वावलम्बन के प्रति सजग है। उद्यमिता के क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन योजना लागू करने के साथ–साथ महिला उद्यमियों को 25.00 लाख तक पूँजी निवेश उपादान तथा छह प्रतिशत तक ब्याज उपादान की व्यवस्था की गयी है।

- सरकार द्वारा जारी नई एमएसएमई नीति के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को विनिर्माणक क्षेत्र में अधिकतम

₹ पाँच लाख एवं व्यवसाय व सेवा क्षेत्र में अधिकतम ₹ तीन लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत करते हुये स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है।

- पारदर्शिता, सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये ई.एम.पार्ट–1 एवं ई.एम.पार्ट–2 के स्थान पर उद्यमियों हेतु उद्योग आधार मैमोरेण्डम ऑनलाइन फाइल करने की व्यवस्था राज्य में लागू कर दी गई है।
- राज्य के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला–संस्कृति को अक्षुण बनाये रखने एवं राज्य के शिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों की सृजनात्मक कला योग्यता को प्रोत्साहित व सम्मानित करने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना" प्रारम्भ की गई है।
- एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत राज्य के अनु0जाति/जनजाति वर्ग के शिल्पियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिल्पों में डिजाइन वर्कशॉप, प्रदर्शनी, सामान्य सुविधा केन्द्र, मार्केटिंग वर्कशॉप, बॉयर–सेलर मीट एवं टूल किट वितरण के प्राविधान किये गये हैं। योजना में प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षित डिजाइनरों की सहायता ली जा रही है।
- सरकार राज्य में हथकरघा एवं प्राकृतिक रेशों के उत्पादों के संवर्द्धन, शोध एवं विकास हेतु प्रयास कर रही है। इस सम्बन्ध में अल्मोड़ा के ग्राम–मटेना में हैण्डलूम एण्ड नैचुरल फाइबर्स केन्द्र स्थापित किया गया है।
- राज्य के परम्परागत शिल्पों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण आदि पर सरकार ध्यान दे रही है। इस हेतु परम्परागत शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा में हरिप्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान स्थापित किया जा रहा है।
- सरकार उत्तराखण्ड ऊन योजना, वित्त पोषित ब्याज उपादान योजना, खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट तथा राज्य के उद्यमियों एवं राज्य के स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामानों के बिक्री हेतु नियमित बाजार उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मेले प्रदर्शनियों के आयोजन कर एक श्रृंखला बनाई गई है जिससे उद्यमियों को वर्ष भर बाजार उपलब्ध कराया जा सके।

- जनता की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने नयी खनन नीति प्रख्यापित कर अवैध खनन/परिवहन की रोकथाम के लिए सार्थक कदम उठाये हैं।

(19) मेरी सरकार पर्यटन को आर्थिकी से जोड़ने के प्रति कटिबद्ध है। उत्तराखण्ड की पर्यटन नीति के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुनियोजित एवं त्वरित समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन संसाधन विकास, प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि पर्यटनोपयोगी गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने पर सरकार बल दे रही है, जिससे उत्तराखण्ड को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सके।

- हमारे प्रदेश का पर्यटन उद्योग दैवीय आपदा 2013 से काफी हद तक उबर गया है। इस वर्ष की चार धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों की संख्या से यह स्पष्ट है कि आपदा पुनर्निर्माण के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर हैं शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन सेक्टर से स्थानीय ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु ''ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना'' अन्तर्गत चिन्हित गाँवों को विकसित करने की कार्यवाही गतिमान है।
- वर्ष पर्यन्त चार धाम यात्रा संचालित किये जाने की दृष्टि से शीतकालीन चार धाम यात्रा शीतकालीन गद्दी स्थलों के लिये प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत यात्रा के सुखद परिणाम आ रहे हैं।
- मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क तीर्थाटन कराया गया है।
- टिहरी झील को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन गन्तव्य के रूप में विकसित किये जाने हेतु मास्टर प्लान बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढावा दिये जाने के उद्देश्य से टिहरी झील में साहसिक पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया।
- जागेश्वर धाम में अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया।

- हैलीकॉप्टर से हल्द्वानी मुन्स्यारी के लिये हवाई सेवा प्रारम्भ की गयी है। इसी भाँति गढ़वाल में भी हैलीकॉप्टर के माध्यम से औली दर्शन योजना भी प्रारम्भ की जा रही है।
- सरकार अन्तर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग इवेन्ट प्रोग्राम पिथौरागढ़ में आयोजित करा रही है।
- **सरकार** विश्व प्रसिद्व चार धाम, पावन तीर्थ हरिद्वार, ऋषिकेश, फूलों की घाटी, मसूरी एवं नैनीताल आने वाले यात्रियों को तीर्थाटन एवं पर्यटन स्थलों हेतु वाहनों को परमिट जारी कर पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान कर रही है।

(20) राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव तथा उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कला आदि का विकास तथा इनका व्यापक प्रचार–प्रसार, पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों का संरक्षण, सर्वेक्षण व अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संग्रहीत कर उनका संरक्षण तथा ऐतिहासिक धरोहर/पुरासम्पदा को सुरक्षित रखना आदि महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया गया है।

- सरकार राज्य की समृद्ध पारम्परिक लोक सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं के रख–रखाव तथा इनके संरक्षण एवं समवर्द्धन में कार्यरत प्रदेश के ऐसे अशासकीय/व्यक्तिगत संग्रहालयों को उनके प्रबन्धन एवं अन्य गतिविधियों के संचालनार्थ आर्थिक अनुदान दिये जाने हेतु योजना संचालित करेगी।
- प्रदेश की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत–पर्वतीय रामलीला, होली, जागर, रम्माण, पण्डवाणी, लोक गाथाएं, लोक कलाओं आदि का वृहद् स्तर पर संरक्षण एवं पोषण करेगी।
- राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक मण्डलों में राज्योत्सव–लोक संगीत, लोक नृत्य, पाककला, ऐंपण आदि की प्रतियोगिता एवं राज्योत्सव के रूप में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- उत्तराखण्ड के गढ़वाल एवं कुमाऊँ क्षेत्र में चैत्र माह की संक्रान्ति के दिन से सम्पूर्ण चैत्र माह में मनाये जाने वाले चैतुला/फुलदेई, हरेला त्यौहार को वृहद स्तर पर आयोजित करेगी।

- स्वामी विवेकानन्द जी की एक सौ पचासवीं जयन्ती की स्मृति में स्वामी जी की तपस्थली शिव मन्दिर, काकड़ीघाट, जनपद अल्मोड़ा में निर्माणाधीन संग्रहालय, पुस्तकालय, ध्यान केन्द्र आदि कार्यों को पूर्ण करेगी।
- देहरादून की पुरानी जेल स्थित नेहरू वार्ड में संग्रहालय, पुस्तकालय तथा सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों का सम्पादन कर, इसे धरोहर के रूप में सहज कर रखेगी।
- सरकार हिमालयन संस्कृति एवं संग्रहालय केन्द्र की स्थापना कर रही है। लोक गायक श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, जागर सम्राट श्री प्रीतम भरतवाण सरीखे प्रख्यात कलाकारों को इससे सम्बद्ध किया जायेगा। जागर विश्वविद्यालय की स्थापना भी प्रस्तावित है।
- कलाकारों के हित संरक्षण हेतु ₹ पाँच करोड़ का कार्पस फण्ड तथा कलाकार बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है।
- सरकार ने राज्य की हितकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुँचे, इस उद्देश्य से गीत–नाट्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न विधाओं के सांस्कृतिक दलों का चयन किया है, जिनके माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक नीतियों, योजनाओं एवं विकास कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय बोली–भाषा में किया जा रहा है और ढोल को सरकार द्वारा राज्य वाद्य यन्त्र के रूप में घोषित किया है।

(21) **सरकार खेलों के प्रति युवाओं का रूझान बढ़ाने का निरन्तर प्रयास कर रही है।** पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान तथा राजीव गाँधी खेल अभियान योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की ओर से प्रतिभाग कर विभिन्न खेलों में पर्याप्त मात्रा में पदक प्राप्त कर राज्य का गौरव बढ़ाया गया।

- राज्य की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले से नियत संख्या में प्रान्तीय रक्षक दल में भर्ती कर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- शिवपुरी स्थित विभागीय राफ्टिंग प्रशिक्षण केन्द्र में युवाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने के लिए राफ्टिंग, आपदा प्रबन्धन व प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सरकार के प्रयासों से एन0एस0एस0 में राज्य में एक स्वयंसेवी को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

(22) सरकार द्वारा वीरता पदक पुरस्कार, द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन, आवासीय सहायता, टॉल फ्री टेलीफोन, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों एवं सैनिक कल्याण की योजनायें संचालित की जा रही हैं।

- सैनिकों के आश्रित पुत्रों को सेना/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण।
- सैनिक विश्राम गृह का संचालन।
- जनपद रूद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल का निर्माण।
- विभिन्न युद्धों, सीमान्त क्षेत्रों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों की विधवाओं/आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

(23) सरकार बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, उनमें कुपोषण, मृत्यदर एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने व माताओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने एवं महिलाओं, किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उन्हें स्वावलम्बी एवं सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है।

- कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कन्या शिक्षा, लिंग भेद को हतोत्साहित करने हेतु उत्तराखण्ड में नन्दा देवी कन्या योजना "हमारी कन्या हमारा अभिमान" योजना संचालित की है।
- महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए निर्भया योजना समस्त जनपदों में लागू की है।
- "घरेलू हिंसा अधिनियम" दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समितियों के क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य में महिलाओ एवं बच्चों के लिये सुरक्षित एवं सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- खिलती कलियाँ योजना के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से छः वर्ष तक की बालिकाओं में कुपोषण दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- पालना योजना के अन्तर्गत परित्यक्त नवजात शिशुओं के पालन हेतु चुनिन्दा स्थानों पर पालनों के रखे जाने का प्रस्ताव है तथा नई जिन्दगी के अन्तर्गत निःशक्त महिलाओं व बालिकाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का शुभारम्भ किया गया है।

(24) औद्योगिक शान्ति के दृष्टिगत श्रमिकों के विधि–सम्मत हित संरक्षण के साथ ही त्वरित औद्योगिक विकास के लिये मेरी सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। राज्य के उद्योगों में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाये रखने की ओर समुचित ध्यान देने के साथ ही समाज के अपेक्षाकृत निर्बल वर्ग के श्रमिकों के हित सम्वर्द्धन के प्रयास हेतु कटिबद्ध है।

- संवैधानिक रूप से स्वास्थ्य का दायित्व राज्य सरकार का होने के कारण स्वास्थ्य सम्बन्धित सेवाओं को लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की है। राज्य में ई0एम0आई0 योजना के तहत चिकित्सालयों से सुविधाएं दी जायेंगी।
- राज्य के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के नियोजकों को सेवायोजन कार्यालय में आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन कर राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

(25) सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से ई–गवर्नेन्स को बढ़ावा दे रही है ताकि जनता को बेहतर जन सुविधाएं प्राप्त हो सकें। इस लक्ष्य के लिए आइ0टी0डी0ए0 द्वारा अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं।

- 'ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना' एवं 'सामान्य सेवा केन्द्र योजना' के अन्तर्गत देवभूमि जनसेवा केन्द्रों का संचालन नागरिकों को सेवायें प्रदान करने हेतु कार्य कर रही है।
- सरकार ने राज्य में 'डिजिटल इण्डिया' पहल का क्रियान्वयन किये जाने हेतु 'नेशनल ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क' का विस्तार राज्य में किया है।

(26) मेरी सरकार कराधान एवं बीमा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत है। सरकार ने व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जिसमें वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹ पाँच लाख भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। यद्यपि मेरी सरकार ने जी0एस0टी0 कर प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को कतिपय सुझाव दिये हैं

तथापि इसके लागू होने पर उसके प्रभाव का आंकलन करते हुए राज्य स्तर पर स्पष्ट नीति बनाए जाने का कार्य कर रही है।

- राष्ट्रीय बचत योजनाओं में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है।
- स्थायी/अस्थायी आमोदों से मनोरंजन कर के माध्यम से पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति की है, जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
- राज्य की जनता को अचल सम्पत्ति के क्रय–विक्रय किये जाने के दृष्टिगत बेहतर सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के अधिकतर उपनिबन्धक कार्यालयों द्वारा कम्प्यूटरीकृत कराया जा चुका है।
- राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्र में अधिवास कर रहे प्रत्येक अर्ह आपदा प्रभावित लाभार्थी, जो स्वयं खरीद की गयी भूमि अथवा दाननामा के माध्यम से प्राप्त भूमि में अपने भवन का निर्माण करना चाहता है, को भूमि की रजिस्ट्री कराये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की है। विलेखों में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा एक हजार रूपये मात्र की गयी है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित व्यक्तियों को बने बनाए मकान क्रय करने की अनुमति दिये जाने का कार्य सरकार कर रही है।
- राज्य सरकार/निजी उद्यमियों द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों से बाहर भू–स्वामियों से उनकी भूमि लीज पर लेने अथवा क्रय करने पर, पट्टा विलेख/ विक्रय विलेख के निबन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, के अन्तर्गत छूट प्रदान की है।
- व्यापारियों के हितों के लिए व्यापारी बीमा योजना को संचालित कर रही है तथा असुविधा न हो एवं पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए व्यापार कार्यालयों में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य सम्पादित कर चुकी है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता लायी जा सकेगी, जी0एस0टी0 कर प्रणाली के लिए भी भविष्य की योजना बना रही है।
- मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की दिशा में सार्थक ऑन–लाइन पेंशन प्रदान करने की योजना को सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न किया है ताकि इसमें पारदर्शिता बनाई जा सके।

- विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत जिला पिथौरागढ़ की नाचनी, अल्मोड़ा की सोमेश्वर, नई टिहरी के नैनबाग एवं बागेश्वर के ढुंगनाकुरी नामक स्थानों में उपकोषागारों की स्थापना की है।
- प्रदेश में स्टाम्प की बिक्री भी ऑन–लाइन होने के कारण स्टाम्प वैण्डरों को बेरोजगारी से बचाने के लिए राज्य में पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं को ई–स्टाम्पिंग के माध्यम से स्टाम्पों की आपूर्ति हेतु स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 के अधीन प्राधिकृत संग्रह केन्द्र (ए0सी0सी0) के रूप में नियुक्त किया गया है।

(27) **इनके अतिरिक्त सरकार निम्नांकित क्षेत्रों में विशेष ध्यान दे रही है:–**

- सचिवालय कार्मिकों / अधिकारियों को उसकी गरिमा के अनुरूप कार्य सम्पादित कराये जाने और दक्षता बनाये जाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- मेरी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य स्तर पर एक वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है, जो एक वर्ष के भीतर इस क्रम में अपनी संस्तुतियाँ राज्य सरकार को देगा।
- सरकार राज्य की जनता को सस्ता, त्वरित एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु देहरादून एवं लक्सर में नये न्यायालय परिसर का निर्माण करा रही है, जिससे वादकारियों एवं अधिवक्ताओं को सुविधा होगी।
- सरकार नें पत्रकारों की सुविधा के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त एवं श्रमजीवी पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भाँति चिकित्सा सुविधा के साथ–साथ राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी दी जा रही है।
- फिल्म निर्माण हेतु शूटिंग स्थलों के विकास, फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार सृजित करने, क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने तथा पूँजी निवेश को आकृषित करने के लिए "उत्तराखण्ड फिल्म नीति" प्रख्यापित की गयी है। जिसके अधीन राज्य में निर्मित एवं प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर में छूट तथा अनुदान की व्यवस्था सम्मिलित है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन

दिये जाने तथा एकल खिड़की व्यवस्था होने की वजह से इस नीति को लेकर निवेशकों में अत्यधिक उत्साह है।

- राज्य की सांस्कृतिक परम्पराओं एवं पर्यटन को देश के मध्य पश्चिम एवं दक्षिण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार तथा राज्य के संवैधानिक पदधारकों, विशिष्ट महानुभावों एवं उच्चाधिकारियों के मुम्बई प्रवास के दौरान उनके गरिमामय अवस्थान हेतु नवीं मुम्बई में राज्य अतिथि गृह एवं इम्पोरियम के निर्माण का निर्णय लिया गया है। इस अतिथि गृह से उत्तराखण्ड वासियों एवं प्रवासी उत्तराखण्डियों को मुम्बई में चिकित्सकीय उपचार, पर्यटन, वाणिज्यिक सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यों हेतु सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त अतिथि गृह के एक भाग को वाणिज्यिक रूप में प्रयोग में लाया जायेगा। इस सन्दर्भ में प्रथम किश्त जारी कर दी गयी है।
- हिन्दी के प्रचार–प्रसार, संवर्द्धन, संरक्षण की पूर्ति हेतु हिन्दी अकादमी तथा भाषा संस्थान के साथ–साथ उर्दू अकादमी तथा पंजाबी अकादमी को स्थापित कर सर्व धर्म सम्भाव का कार्य कर रही है।
- राज्य में अपराधों का संज्ञान करते हुये रोकथाम करना, शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, पर्यटन को बढावा देना, सुरक्षित पर्यावरण बनाये रखना, मानवाधिकारों का संरक्षण तथा जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गयी है।
- सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं के दृष्टिगत संगठित अपराधियों के विरूद्ध योजनाबद्ध कार्यवाही, अवैध खनन पर रोक, अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश, वन्य जीवों का संरक्षण, उद्योगों के विकास हेतु अनुकूल कानून–व्यवस्था, पर्यटन के विकास हेतु सुरक्षित वातावरण तथा सुगम यातायात व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया है।
- महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रति पुलिस बल को विशेष रूप से संवेदनशील और सक्रिय किया है इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु पुलिस मुख्यालय में राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है।
- राज्य में प्राकृतिक आपदा एवं दुर्घटनाओं के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन हेतु ''राज्य आपदा प्रबन्धन बल'' का गठन किया गया है।

- प्रोफेशनल पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में देहरादून, हरिद्वार शहर व हल्द्वानी जनपद नैनीताल की यातायात व्यवस्था तथा स्ट्रीट क्राइम पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु ''सिटी पेट्रोल यूनिट'' का गठन किया जा चुका है। यूनिट द्वारा किये गये कार्यों की माननीय उच्चतम न्यायालय की ''ट्रैफिक कमेटी'' द्वारा भी प्रशंसा की गयी है।
- सरकार द्वारा राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ''अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई'' गठित की है। अवैध खनन में संलिप्त वाहनों के विरूद्ध भी कार्यवाही कर जुर्माना राशि अधिरोपित कर वसूली की गई है।
- मेरी सरकार ने भूमि विवादों से सम्बन्धित अभियोगों की विवेचना एवं शिकायती प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु एस.आई.टी. का गठन किया है, जिसके द्वारा विगत वर्ष के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष शीघ्रता से कार्यवाही कर इकसठ प्रकरण सिविल न्यायालय को स्थानान्तरित किये गये।
- भारत सरकार की सहायता एवं दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत मेरी सरकार ने संचालित सी.सी.टी.एन.एस. प्रोजेक्ट के अन्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में गो–लाईव सम्पन्न किया गया। हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि उत्तराखण्ड राज्य सी0ए0एस0 के साथ सी.सी.टी.एन.एस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन करने वाले राज्यों में अग्रणी राज्यों में सम्मिलित है।
- राज्य के चार पुलिस मॉर्डन स्कूलों के विकास के साथ–साथ पुलिस मॉर्डन स्कूल देहरादून में चाइल्ड केयर सेण्टर की स्थापना भी की जा चुकी है।
- गुमशुदा बच्चों की खोज हेतु राज्य में ऑपरेशन स्माइल का अभियान चलाया गया है, जिसके अन्तर्गत कई गुमशुदा बच्चों को खोजकर उनके परिवार के सुपुर्द किया है। पुलिस द्वारा नेत्रदान महादान जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे नेत्रहीन व्यक्तियों के जीवन में पुनः रोशनी लाने का प्रयास किया जा रहा है।
- आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के लिए अधिकांश विभागों की शासकीय सम्पत्तियाँ "जहाँ हैं, जैसी हैं" के आधार पर हस्तान्तरित हो चुकी हैं, अन्य विभाग यथा सिंचाई विभाग, वित्त, औद्योगिक विकास, कृषि, समाज कल्याण, ऊर्जा, वन, चीनी एवं गन्ना विकास, खाद्य विभाग के प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निरन्तर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

- सरकार ए0पी0एल0 योजना, बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय अन्न योजना की जिम्मेदारी से पालन कर रही है।
- आम जनों के लिए चीनी, मिट्टी तेल, गेहूँ, धान खरीद, चावल, के लिए त्वरित कार्यवाही कर रही है।
- मेरी सरकार द्वारा आमजन की माँग के अनुसार तहसील, उप तहसील और राजस्व ग्रामों का गठन किया गया हैं इससे चौहत्तरवें संविधान संशोधन के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
- सरकार ने राज्य में शत् प्रतिशत मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार कर लिये हैं। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का प्रकाशन भी किया गया है।
- पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा कार्य योजना–प्रथम चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव हेतु शीघ्रता से कार्यवाही कर रही है।
- सरकार द्वारा निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता के मानकों के अनुरूप गत वर्ष एकाधिक चयन प्रक्रियाएँ पूर्ण की गयी हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिविजन), उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर, सफाई निरीक्षक, शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ विश्लेषक (खाद्य), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सहायक निदेशक, रेशम विभाग के 03 अधीक्षक, समाज कल्याण विभाग प्राचार्य समाज कल्याण विभाग तथा राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त राजकीय इण्टर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा द्वारा महिला शाखा के अन्तर्गत विषयों तथा सामान्य शाखा के विषयों में सुयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
- स्थानीय युवाओं को रोजगार दिये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लगभग दो हजार एक सौ पदों हेतु चयन की कार्यवाही गतिमान है।
- संवैधानिक प्राविधानों द्वारा प्राविधानित अनुसूचित जाति, जनजातियों के अधिकारों को संरक्षित करने, उत्पीड़न व शोषण से बचाने, शैक्षिक व आर्थिक स्तर बढ़ाने और सामाजिक समानता दिलाकर राज्य की मुख्य धारा में इन वर्गों को जोड़ने के लिए

सरकार कटिबद्ध है तथा इन वर्गों के कल्याण हेतु चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार प्रयासरत है।

- मेरी सरकार निर्बल वर्गों, वंचित एवं असहाय लोगों के भरण–पोषण के प्रति संवेदनशील है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुसूचित जाति/जनजातियों के छात्रों हेतु शैक्षिक कार्यक्रम, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था, पुत्री के विवाह तथा बीमारी के ईलाज हेतु आर्थिक सहायता, गौरादेवी कन्या–धन योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, अटल आवास योजना, जनजाति सलाहकार परिषद्, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निर्माण, संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत आर्थिक सहायता, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये संचालित कल्याणकारी योजनायें, विकलांग जनों के कल्याणार्थ संचालित योजनायें, निराश्रित विधवा भरण–पोषण अनुदान/विकलांग को भरण–पोषण अनुदान/वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना, तीलू रौतेली पेंशन, बौना समाज पेंशन, पुरोहित पेंशन, कलाकार पेंशन, पत्रकार पेंशन, शिल्पी पेंशन, बाजीगर पेंशन, जगरिया पेंशन प्रारम्भ की गयी हैं।
- विकलांग जनों के लिए नगर क्षेत्रों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्रों में व्यवसायिक फण्ड निर्मित किये जायेंगे।
- अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु छात्रवृत्ति योजनायें, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट की योजना, अल्पसंख्यकों के विकास हेतु वित्त एवं विकास निगम की स्थापना आदि कार्य कर रही है।
- मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी साथ–साथ करा रही है ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक नागरिक कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्रों से सक्रिय रूप से जुड सकें।
- सरकार ने राज्य गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य कार्मिकों के आवंटन की प्रक्रिया

के अन्तर्गत अधिकांश कार्मिकों के आंवटन का कार्य भारत सरकार द्वारा गठित राज्य परामर्शीय समिति के स्तर से पूर्ण कराया जा चुका है।

- परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में राज्य में नियोजन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नीति नियोजकों तथा प्रख्यात संस्थाओं राज्य में सेण्टर फॉर पॉलिसी प्लानिंग एवं गुड गवर्नेन्स की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पूर्व में गठित पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप को इसमें समाहित किया जायेगा।

- नियोजित विकास के महत्व को देखते हुए वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता रहा है। योजना आयोग के माध्यम से वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनायें अनुमोदित की जाती थी। योजना आयोग को वित्तीय संसाधनों के आवंटन का अधिकार था तथा विशेष श्रेणी राज्यों की बजटीय व्यवस्था का आंकलन तथा उनकी विशेष समस्याओं का संज्ञान योजना आयोग द्वारा लिया जाता था। योजना आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य के योजनागत व्यय हेतु वित्तीय संसाधनों का निर्धारण होता था। अब भारत सरकार के स्तर पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जा चुकी है परन्तु नीति आयोग की भूमिका मात्र समन्वयक तथा परामर्शक रह गयी है। यद्यपि नीति आयोग में पूर्वोत्तर राज्यों तथा 03 हिमालयी राज्यों हेतु एक कार्यदल गठित किया गया है तथा एक प्रकोष्ठ प्रस्तावित है तथापि उत्तराखण्ड सरीखे पर्वतीय राज्य की विशिष्ट समस्याओं हेतु नीति आयोग को अन्ततः एक सटीक व्यवस्था करनी होगी।

- यद्यपि 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार कर अन्तरण में राज्य का अंश 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत किया गया परन्तु साथ ही एस0पी0ए0, एस0सी0एस0 तथा एन0सी0ए0 इत्यादि अनुदानों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस कारण हमारे राज्य को पिछले वर्ष की अपेक्षा ₹ 1500 करोड़ से अधिक का घाटा हुआ है। मेरी सरकार द्वारा विभिन्न मंचो के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। यह भी अनुरोध किया है कि दो तिहाई से अधिक भू–भाग पर वनों के संरक्षण के कारण विकास की गतिविधियाँ बाधित हुई हैं। भारत सरकार को पर्यावरण संरक्षण में हमारे योगदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी पारिस्थितिकी सेवाओं के मूल्य को वित्तीय संसाधनों के अन्तर्राज्यीय आवंटन में स्थान देना चाहिये। जब तक इस

सम्बन्ध में कोई फॉरमूला नही बनता भारत सरकार को "ग्रीन बोनस" के तौर पर राज्य को सहायता करनी चाहिये। इस सदन द्वारा पूर्व में सर्वसम्मति से इस सम्बन्ध में संकल्प भी पारित किया गया है।

- केन्द्र सरकार के स्तर पर नियोजन की परिवर्तित परिस्थितियों में भी राज्य में विकास की गति को बनाये रखने तथा केन्द्रपोषित योजनाओं व बाह्य सहायतित योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में मेरी सरकार राज्य की माँग के अनुसार योजनाओं के चयन, प्राथमिकता निर्धारण, तैयारी सहित उनके समय से क्रियान्वयन, सघन अनुश्रवण व बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करेगी।
- मेरी सरकार योजनाओं के समुचित मूल्यांकन व अनुश्रवण के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करायेगी तथा मानव विकास सूचकांकों में गुणात्मक सुधार करेगी। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों के सापेक्ष विकास सूचकांकों को केन्द्र में रखकर कार्य करेगी।
- राज्य की विशेष भौगोलिक स्थिति व जन सांख्यिकीय स्थिति के दृष्टिगत राज्य में यद्यपि लोक निजी सहभागिता के अन्तर्गत निवेश एवं सेवा प्रदाय व्यवस्था के सीमित अवसर हैं, तथापि विगत समय में इस सम्बन्ध में प्रारम्भ किये गये कतिपय प्रयासों का अच्छा अनुभव रहा है जबकि कुछ मामलों में प्रयासों के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं। परन्तु राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधन एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी सरकारी/अर्द्धसरकारी तन्त्र की सीमाओं के दृष्टिगत माँगपूर्ति की अपेक्षाओं को समय से हल करने के लिये मेरी सरकार लोक नीति सहभागिता पद्धति का उपयोग करेगी।
- मेरी सरकार इस हेतु आंकड़ों के एकत्रीकरण, परीक्षण व संकलन सहित इस सम्बन्ध में मानव संसाधन एवं ढ़ांचागत सहित अन्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण व क्षमता वृद्धि का प्रयास करेगी। इस सम्बन्ध में सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जायेगा।
- भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण के माध्यम से भागीरथी एवं भिलंगना नदी घाटी क्षेत्र हेतु महायोजना निरूपण का कार्य प्रगति पर है। इस महायोजना को शीघ्र अन्तिम रूप प्रदान करने के साथ ही प्रक्षेत्रीय योजना बनाते हुए क्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों से समन्वय रखते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करेगी।

- शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सरकार मुख्यमंत्री शिकायत निवारण दिवस मना रही है और गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम लागू है और अधिक पारदर्शिता हेतु लोकायुक्त के चयन की प्रक्रिया गतिमान है।
- सरकार इस वित्तीय वर्ष में 30,000 से अधिक पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग आदि के माध्यम से नियुक्तियाँ किया जाना प्रस्तावित है।

मैनें अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखा। मुझे आशा है कि आप इस गरिमामयी सदन में राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देंगे तथा आपसी सहयोग और सामंजस्य से राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में सफल होंगे। साथ ही विधान सभा सत्र के दौरान अपने समय का अधिकाधिक उपयोग जन समस्याओं के समाधान एवं प्रदेश के विकास की दिशा तय करने में अपनी विद्वता का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। मैं सम्मानित सदस्यगणों का आभार व्यक्त करते हुए वित्तीय और अन्य विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिन्द!